

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

4061
16-05-16

संकल्प

विषय :- भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं विगत वर्षों की बकाया छात्रवृत्ति की राशि के भुगतान तथा प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत आगामी वर्षों में नवीकृत छात्रों के पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए दर की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना, गैर योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/ संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

2. यह योजना राज्य के अंदर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से संचालित है।

3. इस योजना के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुख्य धारा में शामिल किया जाता है तथा उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा, जिनके माता पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000/-रु० (दो लाख पचास हजार रु०) तक हो, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य सरकार के सात निश्चय के अनुपालन में "स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड" (Student Credit Card) के तहत छात्रों को लाभान्वित किया जाना है।

4. राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य के अन्दर एवं बाहर सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था और राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी शिक्षण संस्थानों तथा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में राज्य के अधिकतम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को लाभ पहुँचाने के लिए शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्कों की छात्रवृत्ति दर की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

5. अतः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(I) भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं विगत वर्षों में राज्य के अन्दर सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर सभी सरकारी एवं मान्यताप्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को संबंधित राज्य के सरकारी संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर छात्रवृत्ति की राशि अनुमान्य की जाएगी।

(II) भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष-2015-16 में एवं इसके पूर्व के वर्षों में राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतम सीमा ₹ 15,000/- के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि की स्वीकृति निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

क्र०	कोर्स की विवरणी	छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क + अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1	विभिन्न +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में इंटरमीडियट कक्षा यथा-आई0ए0/आई0एस0सी0/आई0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 2000/-
2	स्नातक स्तरीय कक्षा यथा-बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 5000/-
3	स्नातकोत्तर कक्षा यथा-एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम/एम0फिल0/पी0एच0डी0 एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 5000/-
4	आई0टी0आई0	₹ 5000/-
5	त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पॉलिटेक्नीक एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	₹ 10000/-
6	व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स, यथा-इंजीनियरिंग/मेडिकल/विधि/प्रबंधन तथा अन्य समकक्ष कोर्स (कृषि को छोड़कर)।	₹ 15000/-

(III) केन्द्रीय सरकारी शिक्षण संस्थानों (यथा-आई0आई0टी0 तथा एन0आई0टी0 में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम कमशः ₹ 90,000/- तथा ₹ 70,000/- की दर) एवं अन्य केन्द्रीय शिक्षण संस्थानों यथा-नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन0आई0एफ0टी0, जे0आई0पी0एम0ई0आर0, ए0आई0आई0एम0एस0 आदि में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम ₹ 75,000/- की दर पर छात्रवृत्ति अनुमान्य होगी एवं निर्धारित शिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क तथा अधिकतम सीमा में जो न्यूनतम होगा, उसी दर पर भुगतये होगा।

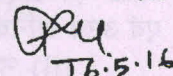
(IV) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की तुलना में सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।

(V) अनुमान्य छात्रवृत्ति राशि के अतिरिक्त समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुरक्षण भत्ता भी देय होगा।

6. उपर्युक्त के अनुपालन के क्रम में विहित प्रक्रिया अन्तर्गत सम्यक् जाँचोपरांत संबंधित पदाधिकारी छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।


आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




16.5.16
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक-5/निदे0(छात्र0)-23-151/16- 4061 पटना, दिनांक- 16/05/16
प्रतिलिपि - अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को संकल्प की दो हार्ड प्रतियों एवं सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि इस संकल्प की 1500 (एक हजार पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।


16.5.16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(छात्र0)-23-151/16- 4061 पटना, दिनांक-16/05/16
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16.5.16
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-5/निदे0(छात्र0)-23-151/16- 4061 पटना, दिनांक- 16/05/16
प्रतिलिपि - सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


16.5.16
सरकार के सचिव।

No.20014/5/2002-Education.
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
Education Division

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated: 23rd May, 2013

To

The Principal Secretary/Secretaries,
Tribal Development Department,
All States/UTs
(Except Haryana, Punjab, Chandigarh, Delhi and Pondicherry)

Subject: Upward revision of the annual parental income ceiling under the Centrally Sponsored Scheme of Post Matric Scholarship for Scheduled Tribe students w.e.f. academic session 2013-14.

Sir,

Kindly refer to my D.O. letter No.20014/33/2012-Education dated 9.4.2013 seeking proposal from your Department for Central Assistance under the Scheme of Post Matric Scholarship for Scheduled Tribe students for the financial year 2013-14. In this context, I am directed to refer to the above mentioned subject and to say that as per the above scheme, the income ceiling would be revised once in every two years linking it with the consumer price index for industrial workers for the month of October of the year, preceding the year of revision and will be made effective from April.

2. Accordingly, it has been decided, with the approval of the Competent Authority, to increase the annual parental income ceiling under the Centrally Sponsored Scheme of Post Matric Scholarship for Scheduled Tribe students from Rs.2.00 lakh to Rs.2.50 lakh per annum w.e.f the academic session 2013-14 (to be effective from 1.4.2013).

3. You are requested to send your proposals for Central Assistance keeping in view the above income ceiling. The proposals, complete in all respects in the proforma prescribed under the scheme and already sent to you vide the D.O. letter mentioned in Para 1 above may please be sent along with the following documents:-

- The utilization certificate of the previous year's released grants.
- Details of the Committed Liability on the State Government/UT Administrations (a proforma attached for ready reference).
- Physical progress achieved during the last financial year.
- Details of preparedness of the States to roll out DBT across the country.

Cont'd....p.2/_

4. I am also directed to invite your attention to the deliberations that took place during the course of consultation with State's Principal Secretaries/ Secretaries/Commissioner-in-Charge/Directors of Tribal Development/Welfare Departments held in New Delhi on May 16-17, 2013 in which compliance of the following key tasks in connection with DBT roll out was discussed:-

➤ **Digitization of data base**

States/UTs must digitize the beneficiary database and covert data in excel sheets to standardized formats developed by the NIC (details available on <http://dbtapp.gov.in>). The digitization of databases should begin in all districts irrespective of the rollout of DBT and States are to report in the meeting complete action on digitization.

➤ **Obtaining of Digital Signature Certificates of designated officers at District and State level**

Obtaining of Digital Signature Certificates (D.S.C.s) for designated offices at district and State level is necessary for verification and authorization of beneficiary list and a necessary condition for the excel sheet to be an authorized data base on which payment decisions will rest. States/UTs were required to urgently designate officials at District and State levels and the designated officials were to apply for Digital Signature Certificate to respective NIC State Unit and contact local NIC officials for training in <http://dbtapp.gov.in>. Compliance of these instructions was to be completed by 30th April, 2013. States may be updated in the meeting.

➤ **Opening of bank accounts of the beneficiaries**

States/UTs may ensure that all ST beneficiaries of the scheme of Post Matric Scholarship for STs have bank accounts. They may urgently pursue with lead banks for speedy opening of bank accounts in respect of beneficiaries which do not yet have accounts in banks with Core Banking System so as to enable payment of scholarship amount into the bank a/c of the beneficiaries.

➤ **Enrolment of beneficiaries for generation of Aadhaar numbers and seeding of bank accounts with Aadhaar numbers.**

The States may in cooperation with UIDAI organize special Aadhaar Enrolment Camps in war-footing for the ST beneficiaries in each district at appropriate location(s) to ensure that all have Aadhaar numbers at the earliest. The existing status may be reported in the meeting. After Aadhaar enrolment of beneficiaries, the States are required to pursue with the lead banks for expediting the Aadhaar seeding of their bank accounts so that payment of scholarships into bank accounts of the beneficiaries can be made through the Aadhaar Payment Bridge (APB).

➤ **Re-engineering of Fund Flow**

The DBT system seeks to ensure that the flow of funds to the beneficiaries under the various schemes is made more efficient by removing such redundant layers which do not contribute value to decision making. There are redundant layers of procedure and sometimes only aggregate data leading to delay and inefficiency. Process re-engineering of the scheme and its architecture is therefore necessary at State level as well as at levels below. This must be in both decision making as well as funds flow. In order to ensure that the State share of the scholarship amount is paid into the bank account of the beneficiary speedily by passing through the minimum number of layers possible, the manner of deciding which levels in government will be part of selection/ authorization process and which levels participate in the fund flow route of the Post Matric Scholarships for STs in each State is to be urgently re-engineered and the Ministry informed of the completion of the exercise.

➤ **Training**

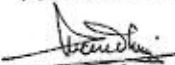
NIC to coordinate training of state/ district level functionaries. State and district teams of trainers to get ready through training by NIC in the next two weeks. Progress on arranging this tie up be reported.

➤ **Monitoring Rollout and reporting of progress in I & II Phase.**

A robust monitoring system for monitoring the rollout should be put in place by the State/UTs and intimated to this Ministry. The States may formulate an Action Plan with timelines for completing the above mentioned preparatory work so as to ensure successful rollout of DBT in the Phase II districts w.e.f. 17.3.2013. Weekly progress report in prescribed format must be provided to the nodal officer DBT in the Ministry by every Thursday.

5. It is requested that your compliance report in respect of the above mentioned key issues may also please be sent immediately to Ms. Shyla Titus, Deputy Secretary (DBT) in this Ministry under intimation to the undersigned.

Yours faithfully,



(Roopak Chaudhuri)

Deputy Secretary to the Government of India

☎: 011-23070508

Copy to File No.20014/33/2012-Education.

Proforma

Proforma of the Committed Liability of the State Governments/UT Administrations for every year of the 12th Five Year Plan period under the Scheme of Post Matric Scholarship for ST students

The **Committed Liability** of the State Governments/UT Administrations for every year of the 12th Five Year Plan is calculated as the total actual expenditure (**State Share + Central Share**) incurred for the year 2011-12 minus additional actual expenditure for the years 2010-11 & 2011-12 paid in during 2011-12, if any, on account of the revision of the Scheme w.e.f. 01-07-2010.

The details may please be furnished as follows:-

[Rs. in lakh]

Total Expenditure incurred (State Share + Central Share) during 2011-12	Rs.
Minus: Additional actual expenditure for the years 2010-11 paid in during 2011-12, if any, on account of the revision of the Scheme w.e.f. 01-07-2010	Rs.
Minus: Additional actual expenditure for the years 2011-12 paid in during 2011-12, if any, on account of the revision of the Scheme w.e.f. 01-07-2010	Rs.
Thus, Committed Liability of the State Government for every year of the 12th Five Year Plan	Rs.

**SCHEME OF POST MATRIC SCHOLARSHIPS TO
THE STUDENTS BELONGING TO SCHEDULED
TRIBES FOR STUDIES IN INDIA**

**REGULATION GOVERNING THE AWARD OF SCHOLARSHIP
(APPLICABLE FROM 01.07.2010)**



**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS
NEW DELHI.**

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS**

**SCHEME OF POST MATRIC SCHOLARSHIPS TO THE STUDENTS
BELONGING TO SCHEDULED TRIBES FOR STUDIES IN INDIA**

**REGULATION GOVERNING THE AWARD OF SCHOLARSHIP
(APPLICABLE FROM 01-07-2010)**

I.

OBJECT

The objective of the scheme is to provide financial assistance to the Scheduled Tribe students studying at post matriculation or post-secondary stage to enable them to complete their education.

II.

SCOPE

These scholarships are available for studies in India only and are awarded by the Government of the State/Union Territory Administration to which the applicant actually belongs i.e. where permanently settled.

III.

CONDITIONS OF ELIGIBILITY

- (i) The scholarships are open to nationals of India.
- (ii) These scholarships will be given for the study of all recognised post-matriculation for post-secondary courses pursued in recognised institutions with the following exceptions :
 - "Scholarships are not awarded for training courses like Aircraft Maintenance Engineer's Courses and Private Pilot Licence courses, courses at Training – Ship Dufferin (Now Rajendra), courses of training at the Military College, Dehradun and courses at pre-examination training centres of all India and State levels."
- (iii) Only those candidates who belong to Scheduled Tribes so specified in relation to the State/Union Territory to which the applicant actually belongs (i.e. permanently settled) and who have passed the Matriculation or Higher

Secondary or any higher examination of a recognized University or Board of Secondary Education, will be eligible.

- (iv) Candidates who after passing one stage of education are studying in the same stage of education in a different subject e.g. I.Sc after I.A. or B.Com after B.A. or M.A. in other subject will not be eligible.
- (v) Students who, after having completed their educational career in one professional line, wish to study for another profession e.g. LLB after B.T./B.Ed. will not be eligible. From the academic year 1980-81, however, studies in two professional courses are allowed.
- (vi) Students studying in Class XI of Higher Secondary Schools which have a continues school course of 12th class will not be eligible. However, in cases where the X class examination of such courses is treated as equivalent to Matriculation and students after passing tenth class can join other courses, such students will be treated as post-matric students and will be eligible for the award of scholarships.
- (vii) Students pursuing post-graduate courses in medicine will be eligible if they are not allowed to practice during the period of their course.
- (viii) Students who after failing or passing the under graduate/post-graduate examinations in Arts/Science/Commerce join any recognised professional or technical certificate/diploma/degree courses will be awarded scholarships if otherwise eligible. No subsequent failure will be condoned except courses in *Group 'I'*, and no further change in the course will be allowed.
- (ix) Students who pursue their studies through correspondence courses are also eligible. The term correspondence includes distant and continuing education.
- (x) Employed students who take leave without pay for the entire duration of the course and study as full time students will be eligible for scholarships.

From the academic year 1980-81, employed students whose income combined with the income of their parents/guardians does not exceed the maximum prescribed income ceiling are made eligible to post-matric scholarships to the extent of reimbursement of all compulsorily payable non-refundable fees.

- (xi) All children of the same parents/guardians will be entitled to receive benefits of the scheme.
- (xii) A scholarship holder under this scheme will not hold any other scholarship/stipend. If awarded any other scholarship/stipend, the student can exercise his/her option for either of the two scholarships/stipends, whichever is more beneficial to him/her and should inform the awarding authority through the Head of the Institution about the option made. No scholarship will be paid to the students under this scheme from the date he/she accepts another scholarship/stipend. The student can however, accept free lodging or a grant or adhoc monetary help from the State Government or any other source for the purchase of books, equipment or for meeting the expenses on board and lodging in addition to the scholarship amount paid under this scheme.
- (xiii) Students who have already received coaching in any of the pre-examination training centres with financial assistance from the Government will not be eligible.

NOTE 1 : Since it is clearly mentioned under the item III (condition of eligibility) of these regulations that the scholarship will be given for the study of all recognised post-matriculation or post-secondary courses pursued in recognised institutions, the list of courses grouped (I to IV) is, thus, only illustrative and not exhaustive. The State Governments/Union Territory Administrations are, thus, themselves competent to decide the appropriate grouping of courses at their level as advised vide Ministry of SJ & E's letter No.11017/13/88-Sch.Cell, dated 3.8.1989.

IV.

MEANS TEST

Scholarships will be paid to the students whose parents/guardians' income from all sources does not exceed **Rs. 2,00,000/- (Rs. two lakh only) per annum.**

NOTE 1: So long as either of the parents (or husband in the case of married unemployed girl student) is alive, only income of the parents/husband, as the case may be, from all sources has to be taken into account and of no other member even

though they may be earning. In the form of income declaration, income is to be declared on this basis. Only in the case where both the parents (or husband in the case of married but unemployed girl student) have died, the income of the guardian who is supporting the student in his/her studies has to be taken. Such students whose parents' income is affected due to unfortunate death of one of earning parents and resultant comes within the income ceiling prescribed under the scheme, shall become eligible for scholarship, subject to their fulfilling other conditions of eligibility, from the month in which such sad incidence takes place. Applications for scholarships from such students can be considered even after lapse of last date of receipt of applications, on compassionate grounds.

NOTE 2: House rent allowance received by the parents of a student shall be exempted from the computation of 'income' if the same has been permitted to be exempted for purpose of Income-tax.

NOTE 3: Income certificate is required to be taken once only i.e. at the time of admission to courses which are continuing for more than one year.

NOTE 4: The revised income ceilings account for Consumer Price Index for Industrial workers **upto October, 2009**. Income Ceiling would be revised once in every two years linking it with Consumer Price Index for Industrial Workers *for the month of October of the year, preceding the year of revision and will be made effective from April.*

V.

VALUE OF SCHOLARSHIP

The value of scholarship includes maintenance allowance, provision for students with disabilities, reimbursement of compulsory non-refundable fees, Study Tour Charges, thesis typing/printing charges and book allowance for students pursuing correspondence courses, for complete duration of the course.

The details are given below:-

(i) **Maintenance Allowance:**

Group	Courses	Rate of Maintenance Allowance (in Rupees per month)	
		Hostellers	Day Scholars
Group I	<p>(i) Degree and Post Graduate level courses including M. Phil., Ph.D. and Post Doctoral research in Medicine (Allopathic, Indian and other recognized systems of medicines), Engineering, Technology, Planning, Architecture, Design, Fashion Technology, Agriculture, Veterinary & Allied Sciences, Management, Business Finance /Administration, Computer Science/ Applications.</p> <p>(ii) Commercial Pilot License (including helicopter pilot and multiengine rating) course.</p> <p>(iii) Post Graduate Diploma courses in various branches of management & medicine.</p> <p>(iv) C.A./I.C.W.A./C.S./I.C.F.A. etc.</p> <p>(v) M. Phil., Ph.D. and Post Doctoral Programmes (D. Litt., D.Sc. etc.) :-</p> <p style="padding-left: 40px;">a) In existing Group II courses</p> <p style="padding-left: 40px;">b) In existing Group III courses</p> <p>(vi) L.L.M.</p>	1200	550

Group II	(i) Graduate/ Post Graduate courses leading to Degree, Diploma, Certificate in areas like Pharmacy (B Pharma), Nursing (B Nursing), LLB, BFS, other para-medical branches like rehabilitation, diagnostics etc., Mass Communication, Hotel Management & Catering, Travel/Tourism/Hospitality Management, Interior Decoration, Nutrition & Dietetics, Commercial Art, Financial Services (e.g. Banking, Insurance, Taxation etc.) for which entrance qualification is minimum Sr. Secondary (10+2). (ii) Post Graduate courses not covered under Group-I e.g. M.A./M.Sc./M.Com./M. Ed./M. Pharma etc.	820	530
Group III	All other courses leading to a graduate degree not covered under Group I & II e.g. BA/B Sc/B Com etc.	570	300
Group IV	All post-matriculation level non-degree courses for which entrance qualification is High School (Class X), e.g. senior secondary certificate (class XI and XII); both general and vocational stream, ITI courses, 3 year diploma courses in Polytechnics, etc.	380	230

NOTE 1: **Commercial Pilot License Course (CPL):** CPL course is covered under Group 'I'. The number of awards for CPL will be 10 per annum. The selection of 10 ST students for CPL course will be made through Directorate General of Civil Aviation (DGCA). Applications for CPL course will be invited through advertisement. Interested ST students may apply for selection for grant of scholarship for pursuing

CPL course. Selected candidates shall be provided a maintenance allowance at rates applicable to Group 'I' courses i.e. **Rs.1200/- per month** for hostelers and **Rs.550/- per month** for day scholars. In addition all compulsory fees, including flight charges are to be provided as fee.

NOTE 2 : M.Phil and Ph.D courses are post-graduation courses. Scholarship to such students may be paid at the rates of maintenance allowance for Group 'I' or 'II' depending on the course under these groups.

NOTE 3 : Normally the term 'Hostel' is applicable to a common residential building and a common mess for the students run under the supervision of the educational institution authorities. In case the college authorities are unable to provide accommodation in the college Hostel, an approved place of residence can also be treated as Hostel for the purpose of this scheme. The place will be approved by the Head of the Institution after due inspection and keeping in view the rules and regulations laid down by the University, if any. In such case, a certificate to the effect that the student is residing in an approved place of residence as he is unable to get accommodation in the college hostel should be furnished by the Head of Institution.

It is further clarified that such deemed hostels should consist of such accommodation as is hired at least by a group of 5 (five) students living together, usually with common mess arrangements.

NOTE 4. Scholars who are entitled to free board and/or lodging will be paid maintenance charge at $1/3^{rd}$ of the rate for Hostellers

(ii) Additional Provision for ST students with disabilities

(A) Reader Allowance for blind Scholars

<u>Level of Course</u>	<u>Reader Allowance (Rs. Per month)</u>
Group I, II	240
Group III	200
Group IV	160

(B) Provision of transport allowance upto Rs.160/- per month for disabled students, if such student does not reside in the hostel, which is within the premises of educational institution. The disability as per the Persons with Disabilities (Equal

Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 is defined as blindness, low-vision, leprosy-cured, hearing impairment, locomotor disability, mental retardation and mental illness.

(C) Escort Allowance of **Rs.160/- per month** for severally handicapped day scholar students with low extremity disability.

(D) Special Pay of **Rs.160/- per month** is admissible to any employee of the hostel willing to extend help to a severely orthopaedically handicapped student residing in hostel of an educational institution, who may need the assistance of a helper.

(E) Allowance of **Rs. 240/- per month** towards extra coaching to mentally retarded and mentally ill students.

The provisions in (B) to (D) will also apply to leprosy -cured students.

Note 1: The disabled students belonging to Scheduled Tribes covered under the Scheme can also get such additional benefits from other Schemes, which are not covered under the scheme.

Note 2: The disability as defined under the said Act has to be certified by competent medical authority of the State Govt./UT Administration.

(iii) Fees

Scholars will be paid enrolment/registration, tuition, games, Union, Library, Magazine, Medical Examination and such other fees compulsorily payable by the scholar to the institution or University/Board. Refundable deposit like caution money, security deposit will, however, be excluded.

NOTE: Compulsory non-refundable fee charged by recognized institutions against free and paid seats of recognized courses can be fully reimbursed as per the fee structure approved by the competent State/Central Government authority. However, while sanctioning scholarship against paid seat, State Governments would make the income verification compulsory.

(iv) Study Tours

Study tour charges upto a maximum of **Rs.1600/- per annum**, limited to the actual expenditure incurred by the student on transportation charges etc. will be paid to the scholars studying professional and technical courses, provided that the head of the institution certifies that the study tour is essential for the scholar for completion of his/her course of study.

(v) Thesis Typing/Printing Charges

Thesis typing/printing charges upto a maximum of **Rs.1600/-** will be paid to research scholars on the recommendation of the Head of the Institution.

(vi) Correspondence courses including distance and continuing education

The students pursuing such courses are also eligible for an annual allowance of **Rs.1200/-** for essential/prescribed books, besides reimbursement of course fees.

VI.

SELECTION OF CANDIDATES

- (i) All the eligible Scheduled Tribes candidates will be given scholarships subject to the application of Means Test prescribed in these Regulations.
- (ii) Candidates belonging to one State but studying in other State will be awarded scholarships by the State to which they belong and will submit their applications to the competent authorities in that State. In the matter of exemption from fees or other concessions also they will be treated as if they were studying in their own State.

VII.

DURATION AND RENEWAL OF AWARDS

- (i) The award once made will be tenable from the stage at which it is given to the completion of course subject to good conduct and regularity in attendance. It will be renewed from year to year provided that within a course which is continuous for a number of years, the scholar secures promotion to the next higher class irrespective of the fact whether such examinations are conducted by a University or the Institution.
- (ii) If a Scheduled Tribe scholar pursuing *Group I* course fails in the examination for the first time, the award may be renewed. For second and subsequent

failure in any class, the student shall bear his/her own expenses until he/she secures promotion to the next higher class.

- (iii) If a scholar is unable to appear in the annual examination owing to illness and/or on account of any other unforeseeable event, the award may be renewed for the next academic year on submission of medical certificate and/or other required sufficient proof to the satisfaction of the Head of the Institution and his/her certifying that the scholar would have passed had he/she appeared in the examination.
- (iv) If according to the Regulations of a University/Institution, a student is promoted to the next higher class even though he/she may not have actually passed in lower class and is required to take examination of the junior class again after sometime, he/she will be entitled to scholarship for the class to which he/she is promoted if the student is otherwise eligible for scholarship.

VIII.

PAYMENT

- (i) Maintenance allowance is payable from 1st April or from the month of admission, whichever is later, to the month in which the examinations are completed, at the end of the academic year (including maintenance allowance during holidays), provided that if the scholar secures admission after the 20th day of a month, the amount will be paid from the month following the month of admission.
- (ii) In case of renewal of scholarship awarded in the previous years, maintenance allowance will be paid from the month following the month upto which scholarship was paid in the previous year, if the course of study is continuous.
- (iii) The Government of the State/Union Territory Administration, to which the student belongs, in accordance with the procedure laid down by them in this regard, will pay the scholarship money to the selected students.
- (iv) Scholarship will not be paid for the period of internship/housemanship in the M.B.B.S. course or for a practical training in other course if the student is in receipt of some remuneration during the internship period or some allowance/stipend during the practical training in other course.

IX.

OTHER CONDITIONS FOR THE AWARD

- (i) The scholarship is dependent on the satisfactory progress and conduct of the scholars. If it is reported by the Head of the Institution at any time that a scholar has by reasons of his/her own act of default failed to make satisfactory progress or has been guilty of misconduct such as resorting to or participating in strikes, irregularity in attendance without the permission of the authorities concerned etc., the authority sanctioning the scholarship may either cancel the scholarship or stop or withhold further payment for such period as it may think fit.
- (ii) If a student is found to have obtained a scholarship by false statements, his/her scholarship will be cancelled forthwith and the amount of the scholarship paid will be recovered, at the discretion of the concerned State Government. The student concerned will be blacklisted and debarred for scholarship in any scheme forever.
- (iii) A scholarship awarded may be cancelled if the scholar changes the subject of the course of study for which the scholarship was originally awarded or changes the Institution of study, without prior approval of the State Government. The Head of the Institution shall report such cases to them and stop payment of the scholarship money. The amount already paid may also be recovered at the discretion of the State Government.
- (iv) A scholar is liable to refund the scholarship amount at the discretion of the State Government, if during the course of the year, the studies for which the scholarship has been awarded, is discontinued by him/her.
- (v) The regulations can be changed at anytime at the discretion of the Government of India.

X.

ANNOUNCEMENT OF THE SCHEME

All the State Governments will announce in May-June, the details of the scheme and invite applications by issuing an advertisement in the leading newspapers of the State and through other media outfits. All requests for application forms and other particulars should be addressed to the Government of State/Union

Territory Administration to which the scholars actually belong. The applicant should submit the completed application to the prescribed authority before the last date prescribed for receipt of applications.

XI.

PROCEDURE FOR APPLYING

- (i) An application for scholarship should comprise:
 - (a) One copy of the application for scholarship in the prescribed form (separate application forms as have been prescribed for 'fresh' and renewal scholarship by concerned States/UTs).
 - (b) One copy of the passport size photograph with signatures of the student thereon (for fresh scholarship).
 - (c) One attested copy of certificates, diploma, degree etc. in respect of all examinations passed.
 - (d) A certificate (in original) of Caste duly signed by **an authorised Revenue Officer** not below the rank of Tahsildar.
 - (e) An income declaration by the self-employed parents/guardians, stating definite income from all sources by way of an affidavit on non-judicial stamp paper. Employed parents/guardians are required to obtain income certificate from their employer and for any additional income from other sources, they would furnish declaration by way of an affidavit on non-judicial stamp paper.
 - (f) A receipt in acknowledgement of the scholarship in the previous year on the form attached to the application only duly counter-signed by the Head of the Institution concerned, if the applicant was in receipt of a scholarship under this scheme in the preceding year.
- (ii) Application complete in all respects shall be submitted to the Head of the Institution, being attended or last attended by the candidates and shall be addressed to an officer specified for this purpose by the Government of State/Union Territory to which the student belongs, in accordance with the instructions issued by them from time to time.

XII.

FUNDING PATTERN OF THE SCHEME

The Scheme is implemented by the State Governments and Union Territory Administrations, which receive 100% central assistance from Government of India, over and above their respective Committed Liability. The level of Committed Liability of respective State Governments/Union Territory Administrations for a year is equivalent to the level of actual expenditure incurred by them under the Scheme during the terminal year of the last Five Year Plan Period and is required to be borne by them for which they are required to make required provision in their own budget. The North Eastern States have, however, been exempted from making their own budgetary provisions towards Committed Liability from Ninth Plan Period (1997-2002) onwards and the entire expenditure under the Scheme in respect of them will be borne by Government of India.

NOTE : Additional Committed Liability on account of the revision of the Scheme w.e.f. 01-07-2010 shall be passed on to State Governments/U.T. Administrations at the end of the XII Five - Year Plan period (w.e.f. 01-04-2017), and not after the XI Plan period.

All the State Governments and Union Territory Administrations implementing the Scheme will:-

- (i) *furnish data of beneficiaries and expenditure under the scheme, to Government of India, regularly in the Quarterly Reports prescribed for this purpose. **Financial assistance given under the Scheme shall not be utilized for any other purpose.***
- (ii) *designation Grievance Redressal Officers (GROs) at the State and District levels to redress students' scholarship-related grievances.*

XIII. BOOK BANK FOR SCHEDULED TRIBE STUDENTS

OBJECT

The object behind the Scheme is to establish Book Banks in each Medical (including Indian systems of Medicine and Homeopathy), Engineering, Agriculture, Veterinary, Polytechnics, Law Course, Chartered Accountancy, MBA and Bio-Sciences to Scheduled Tribe students who can not afford expensive education but for adequate state support. The inability of these students to buy costly text books, results in large number of failures and drop outs which retards the upliftment of Scheduled Tribes.

SCOPE

These 'Book Banks' are to be set up in all the Medical, Engineering, Agriculture, Law and Veterinary Degree Colleges and Institutes imparting Chartered Accountancy, MBA and alike Management Courses and Polytechnics where Scheduled Tribe students receiving Post Matric Scholarship under the Centrally Sponsored Scheme of Post Matric Scholarship to Scheduled Tribes for studies in India belonging to the parent state or from other state, are studying. Purchase of books for these 'Book Banks' will be restricted to the prescribed text books for the entire courses for recognized Medical, Engineering, Agriculture, Veterinary, Law Courses, Chartered Accountancy, MBA, Bio-Sciences and Polytechnic courses being pursued by ST students therein. The set of text books will be purchased for 2 such ST students at various stages except in respect of Post-graduate courses and Chartered Accountancy where it will be one set for each student. However, the ratio of sets and students will have to be adjusted to the total number of sets that could be procured within the total resources allocated to the State concerned. The State Government may constitute an expert group consisting of members from selected colleges of different regions to decide the adequate number of text books in a set (not reference books) required for each course. Thereafter estimate may be worked out keeping in view the price of cheap Indian editions. The State Government may

constitute a set within the total cost of text books. The life period of one set of books has been fixed at 3 years.

XIV. COURSE-WISE PATTERN OF ASSISTANCE

Central assistance to States/UTs for setting up of Book Banks is limited to the following ceiling or actual cost of a set, whichever is less:-

I. Degree Courses

Cost of one set

(1 set for 2 students)

1.	Medical	Rs. 7,500/-
2	Engineering	Rs. 7,500/-
3.	Veterinary	Rs. 5,000/-
4.	Agriculture	Rs. 4,500/-
5.	Polytechnic	Rs. 2,400/-

II. Post-Graduate Course

(A). Post Graduate courses in Medical, Engineering, Agriculture and Veterinary courses and such other technical/alike courses as are approved by the Universities/Institutes of higher learning.	Rs. 5,000/- 1 set per student
(B). Law courses, L.L.B. (3 years and 5 years) L.L.M. (2 years)	Rs. 5,000/- 1 set per student
(C). Chartered Accountancy (inter-mediate and final)	Rs. 5,000/- 1 set per student
(D). M.B.A. (2 years) and similar courses	Rs. 5,000/- 1 set per student
(E). Bio-Science	Rs. 5,000/- 1 set per student

Note: The said sets of books will also include Braille Books, Talking Books, Cassettes for the visually Handicapped students.

The essential books purchased, limiting the amount to the ceilings indicated above are to be supplied to the ST students in instalments, depending on the course, semester structure etc.

The life span of one set of books has been fixed at 3 years so as to ensure that Book Banks beneficiaries have access to the latest books/editions. At the end of 3 years these books may be kept in the library of the concerned institution for loan to other ST students until such time as the books remain relevant and serviceable. Thereafter the books may be disposed off by the institution in the same manner as the books in the library subject to the guidelines, if any, of the State Government/UT Administration in this regard. Purchase of text books for these Book Banks is restricted to the prescribed text books for the entire course referred to above.

XV. PREFERENCE TO GIRL STUDENT AND HANDICAPPED STUDENTS

While selecting students for 'Book Bank' Scheme the State/UT should set a target to be implemented, wherever possible, that at least 30% of the beneficiaries are girl ST students and at least 3% disabled ST students.

XVI. FINANCIAL ASSISTANCE

Central assistance for the setting up of 'Book Banks' will be given for the purchase of prescribed text books for Medical, Engineering, Agriculture, Veterinary and Polytechnic courses and Post-Graduate courses in Medical, Engineering, Agriculture, Veterinary courses and such other technical/alike courses as are approved by the Universities/Institutions of higher learning, Law Courses, Chartered Accountancy (Inter-mediate and final), MBA and Bio-Sciences limited to the amount as indicated above or actual cost of a set, whichever is less.

For storage of books and contingencies etc., the cost of steel almirah for storing books of each 'Book Banks' including contingencies like transportation etc. the following expenses are admissible.

- (i) Rs. 2000/- or actual cost whichever is less.

- (ii) 5% of the grant may be earmarked for expenses on binding, stitching etc.

XVII. PLACEMENT OF FUNDS AND ADMINISTRATION OF THE SCHEME

The total expenditure on the scheme of 'Book Banks' will be shared between the Central and the State Government on matching grant basis (50:50) (100% central assistance to the UT Administration). State Govt. may consider making the Heads of the Institutions responsible for the running of the Scheme and place funds at their disposal.

XVIII. SUBMISSION OF DATA

The State Governments UT Administrations will inform the Government of India about the amount allotted college-wise specifying the number of sets to be purchased for that college and the number of beneficiaries.

XIX. UTILIZATION OF FUNDS

Financial assistance given under the Scheme shall not be utilized for any other purpose. If the college concerned fails to utilize the grant for the purpose for which it is given, the amount shall be refunded to the Central Government. The State Government/UT Administration should furnish statement of Expenditure and Utilization Certificates.

XX. DISTRIBUTION OF BOOKS TO STUDENTS

The following rules shall govern the distribution of books to the students:

- (i) Each ST student will be provided with an identity card for this purpose.
- (ii) Each ST student will be required to submit the requisition for borrowing books from the Book Bank in a form to be provided for this purpose.
- (iii) Books will be suitably distributed among the ST students keeping in view the norm that one set is meant for 2 students for the entire course, except in respect of Post-Graduate courses and other courses as stated in para XIV (I) & XIV (II) above.

- (iv) The books should be returned to the Book Bank at the end of each term. The Principal of the College/Institution will make every effort to ensure that those students who complete their course or those who drop out in the middle, return the books belonging to the Book Bank.
- (v) It is the responsibility of the student concerned to maintain the books supplied to them from the Book Bank, in good condition.
- (vi) Any case of loss or damage to the books would attract penalty. In case of serious damage or loss of books, the student concerned will have to bear the cost of the book.

....X....

REFERENCES :

Sl. No.	Para number of Regulations	No. and date of letter of Ministry of SJ&E.
1	III(v)	No.11917/37/79/SC&BCD-III dated 20-6-1980
2	III(x)	No.11017/23/-80-SC&BCD-III dated 21-6-1980
3	III(xi),III((xii)	No.11017/4/97-SCD-V dated 10-7-1998
4	IV Note 1	No.11017/2/94-Sch.Cell dated 29-12-1995
5	IV Note 2	No.11017/1/92-Sch.Cell dated 14-2-1996
6	IV Note 3	No.11017/10/94-Sch.Cell dated 22-7-1994
7	IV Note 4	No.11017/8/97-Sch.Cell dated 3-4-1998
8	V Group 'A' (I)	No.11017/1/93-Sch.Cell dated 7-4-1995
9	V(I) Note 1	1. No.11017/2/91-Sch.Cell dated 24-7-1992 & 2. No.11017/9/91-Sch.Cell dated 1-2-1994
10	V(I) Note 2	No.11017/2/92-Sch.Cell dated 8-4-1994
11	V(I) Note 3	No.11017/11/93-Sch.Cell dated 31-3-1995
12	XI	No.11017/4/97-SCD-V dated 10-7-1998
Ministry of Tribal Affairs' Circular		
13	V (i),(ii),(iv)(v), (vi) IV, XIII	No. 20014/10/2000-TDA (Vol. III) dated 19-2-2004.
14	V (iii)	No. 20014/10/2000-TDA (Vol. IV) dated 29-5-2006
15	V (i) Note 1.	No. 20014/4/2006-Education dated 9-8-2006
16	IV	No. 20014/5/2002-Scheme/Education dated 3-7-2007
17	V (iii)	No. 20014/10/2000-Education (Vol. IV) dated 5-7-2007
18	V (iii)	No.19012/85/2006-Education dated 28-9-2007
19	V (iii)	No.19012/85/2006-Education dated 27-11-2007
20	XII	No. 20014/1/2007-Education dated 19-12-2007
21	V (iii)	No.19012/85/2006-Education dated 04-03-2008
